



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, मंगलवार, 24 अप्रैल, 2007/4 वैशाख, 1929

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, शिमला

अधिसूचना

शिमला-171 002, 13 अप्रैल 2007

संख्या एच० पी० ई० आर० सी०/428.—हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग की 30 नवम्बर, 2005 तारीख की समसंख्यांक अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य में किसी व्यक्ति को उर्जा के नवीकरणीय स्रोतों तथा सह-उत्पादन से विद्युत के विक्रय तथा उर्जा के नवीकरणीय स्रोतों तथा सह-उत्पादन से वितरण अनुज्ञापतिधारी द्वारा विद्युत उपापन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित संशोधित प्रारूप विनियम, जिन्हें हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 86 की उप-धारा (1) के खण्ड (ड) तथा धारा 181 की उप-धारा (1)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करता है, एतद्वारा विद्युत (पूर्व प्रकाशन के लिए प्रक्रिया) नियम, 2005 के नियम 3 तथा उक्त अधिनियम की धारा 181 की उप-धारा (3) द्वारा यथोपेक्षित के अनुसार उनसे आम प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिये प्रकाशित किए जाते हैं और एतद्वारा यह नोटिस (सूचना) दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर, इनके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से तीस (30) दिन के अवसान पर किसी भी आक्षेप या सुझाव सहित, जो इस बाबत उक्त अवधि के भीतर प्राप्त हुआ हो/हुए हों, विचार किया जाएगा।

इस निमित्त आक्षेप या सुझाव सचिव, हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, क्वॉथल कमर्शियल काम्पलेक्स, खलिनी, शिमला को सम्बोधित किए जाने चाहिए।

### प्रारूप विनियम

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ.— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उर्जा के नवीकरणीय स्रोतों तथा सह-उत्पादन से विद्युत उपापन) विनियम, 2007 है।

(2) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.— इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) “आयोग” से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(ग) “अन्तरायोजन बिन्दु” तथा “अन्तरायोजन सुविधाएं” के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उर्जा के नवीनकरणीय स्रोत तथा सह-उत्पादन से उर्जा उत्पादित करने वाले व्यक्ति द्वारा निष्पादित विद्युत उपापन करार में दिए गए हैं;

(घ) “नवीकरणीय स्रोत तथा सह-उत्पादन” से इस संदर्भ में, गैर-पारंपरिक उर्जा उत्पादन स्रोत, अभिप्रेत है जिनमें 25 मैगावाट की/तक की क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाएं, पवन, सौर, जैव द्रव्यमान अनुपाती अभिक्रिया शहरी/नगरीय कचरा स्रोत तथा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दूसरे अन्य स्रोत भी आते हैं;

(ङ.) “राज्य” से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है; तथा

(च) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और यहाँ परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में नियत किए गए

हैं; उन पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं परन्तु विशेष रूप में इन विनियमों में अथवा अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु सक्षम विधानमण्डल द्वारा पारित और राज्य में विद्युत उद्योग में लागू किसी विधि में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उक्त विधि में नियत किये गए हैं; उन पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं परन्तु विशेष रूप से इन विनियमों में अथवा अधिनियम में अथवा सक्षम विधान मण्डल द्वारा पारित विधि में परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो सामान्यतः उनके लिए विद्युत उद्योग में दिए जाते हैं ।

**3. उर्जा नवीकरणीय स्रोत अभिवृद्धि.—** कोई भी व्यक्ति, जो उर्जा नवीकरणीय स्रोतों तथा सह-उत्पादन से विद्युत उत्पादन करता है, स्थापित क्षमता का विचार किए बिना, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण प्रणाली और/या वितरण प्रणाली या ग्रिड तक हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (खुली पहुँच हेतु निबन्धन एवं शर्तों) विनियम, 2005 के अन्तर्गत आदेशात्मक खुली पहुँच का हकदार होगा । उक्त व्यक्ति के आवेदन पर, यथास्थिति, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य पारेषण उपयोगिता, समुचित अन्तरायोजन सुविधाएं उपलब्ध करेगा तथा उक्त सुविधाएं विद्युत को ग्रिड से जोड़ने के लिए प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट मानकों के अनुकूल होंगी:

परन्तु यह कि उर्जा के नवीकरणीय स्रोत तथा सह-उत्पादन से उर्जा उत्पादन करने वाला व्यक्ति केवल अन्तरायोजन बिन्दु तक ही उस द्वारा संयोजन पर किए गए व्यय का वहन करेगा तथा यथास्थिति वितरण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा अन्तरायोजन बिन्दु से आगे पारेषण/उप-पारेषण प्रणाली से विद्युत निकासी हेतु संवर्धन पर व्यय, यदि कोई हो, का वहन किया जाएगा ।

(2) उर्जा के नवीकरणीय स्रोत तथा सह-उत्पादन से विद्युत उत्पादक, अन्तरायोजन बिन्दु से आगे विद्युत निकासी हेतु संकर्मों की लागत के 50 प्रतिशत के बराबर, यथास्थिति, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा राज्य पारेषण उपयोगिता, को ब्याज रहित ऋण देगा और इस प्रयोजन हेतु संकर्म लागत आयोग द्वारा अनुमोदित लागत आँकड़ों पर आधारित होगी:

परन्तु यदि पारेषण प्रणाली से विद्युत निकासी हेतु अन्तरायोजन बिन्दु से आगे, एक से अधिक उर्जा के नवीकरणीय स्रोत तथा सह-उत्पादन से उर्जा उत्पादक भागीदार हों, तो नवीकरणीय स्रोत तथा सह-उत्पादन से उर्जा उत्पादकों को प्रदत्त ऋण राशि परियोजनाओं की पूंजी लागत के अनुपाततः होगी ।

(3) यथास्थिति वितरण अनुज्ञप्तिधारी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या राज्य पारेषण उपयोगिता, परियोजना के चालू होने के एक वर्ष के उपरान्त, पाँच वर्षों में, पांच समान किश्तों में नवीकरणीय स्रोत तथा सह-उत्पादन से उर्जा उत्पादक (कों) को ब्याज रहित ऋण राशि प्रतिसंदत करेगा ।

(4) नवीकरणीय स्रोत तथा सह-उत्पादन से प्राप्त उर्जा को, ग्रिड के माध्यम से जोड़ने, पारेषण अथवा चक्रण को अधिमान दिया जाएगा।

(5) वितरण अनुज्ञप्तिधारी उर्जा अधिकोषण अनुज्ञात करेगा।

**4. नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत क्रय मात्रा.—**(1) आबद्ध उपयोग तथा राज्य से बाहर तीसरे पक्ष को विक्रय के बाद, बची उर्जा नवीकरणीय स्रोत तथा सह-उत्पादन से उर्जा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा क्रीत की जाएगी:

परन्तु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में उर्जा के नवीकरणीय स्रोतों और सह-उत्पादन से उर्जा की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए, इन विनियमों के अधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उर्जा के नवीकरणीय स्रोतों तथा सह-उत्पादन से प्राप्त उर्जा की न्यूनतम विद्युत क्रय मात्रा, वर्ष में उसकी कुल खपत की 20 प्रतिशत होगी।

**स्पष्टीकरण.—**इस विनियम के प्रयोजनों के लिए “क्रय मात्रा” नवीकरणीय स्रोतों तथा सह-उत्पादन से प्राप्त उस उर्जा का योग होगी जो सह-उत्पादन, उर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित उत्पादन केन्द्रों तथा अन्य अनुज्ञप्तिधारी से सीधे क्रय की जाती है।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपनी राजस्व गणना दाखिल करते समय आगामी वर्ष के लिए नवीकरणीय स्रोतों तथा सह-उत्पादन से अपनी क्रय मात्रा का, पर्याप्त प्रमाण सहित, उल्लेख करेगा।

(3) आयोग, प्रत्येक तीन वर्ष के अन्तराल में एक बार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए नवीकरणीय स्रोत तथा सह-उत्पादन से नियत क्रय मात्रा को पुनर्निरीक्षित कर सकेगा:

(4) आयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर, प्रदाय की मजबूरियों तथा अन्य अनियन्त्रित कारणों के अध्यधीन रहते हुए, उप-विनियम (1) में अधिकथित क्रय मात्रा का अधित्यजन कर सकेगा।

**5. टैरिफ का अवधारण.—**(1) 25 मैगावाट की/तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपापन की जाने वाली उर्जा के लिए टैरिफ, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रचलित जल विद्युत नीति के अनुसार होगा।

(2) उप-विनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, 5 मैगावाट की/तक की लघु विद्युत परियोजनाओं से नवीकरणीय उर्जा उत्पादक, आयोग को टैरिफ अवधारण के लिए आवेदन दे सकेंगे और आयोग, टैरिफ अवधारण करते हुए, इन विनियमों के उपाबन्ध में दी गई लागत आधारित

संदर्भिका पर विचार करेगा तथा अधिनियम की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति, तथा केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट सिद्धांत और विचारधारा तथा ऐसे टैरिफ अवधारण के लिए केन्द्रीय आयोग द्वारा अधिसूचित निबन्धनों एवं शर्तों से मार्गदर्शित होगा:

परन्तु यह कि आयोग, पर्याप्त कारण देकर तथा सम्यक् तत्परता बरतते हुए तथा प्रज्ञायुक्त जांच करके, केन्द्रीय आयोग द्वारा अधिसूचित उत्पादन टैरिफ के निबन्धनों एवं शर्तों को बदल सकता है;

परन्तु और यह कि आयोग, टैरिफ अवधारित करते समय, लघु जल विद्युत परियोजना की प्रौद्योगिकी के स्वरूप, बाजार जोखिम पर्यावरिक हित तथा समाजिक योगदान इत्यादि के आधार पर, सम्भवनीय मात्रा में छूट दे सकेगा।

(3) इन विनियमों के उपाबन्ध में दी गई संदर्भिकाएँ तीन वर्षों में एक बार, पुननिरीक्षित की जाएगी।

(4) आयोग द्वारा अधिकथित संदर्भिकाओं के अध्यधीन रहते हुए, उर्जा के नवीकरणीय स्रोतों तथा सह-उत्पादन से अन्य उर्जा का टैरिफ ऐसा होगा जैसे आयोग, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निर्दिष्ट करे और ऐसा करते समय, आयोग राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति से मार्गदर्शित होगा।

6. **अध्यारोही प्रभाव.**—विद्युत अधिनियम, 2003, की धारा 181 के अधीन बनाए गए—

(क) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिए निबन्धन और शर्तों) विनियम, 2004, तथा

(ख) हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (खुली पहुँच हेतु निबन्धन एवं शर्तों) विनियम, 2005 में, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इन विनियमों के उपबन्धों का अध्यारोही प्रभाव होगा।

7. **कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.**—यदि इन विनियमों में किसी उपबन्ध को लागू करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है, तो आयोग, स्वतः अथवा आवेदन पर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी समुचित कार्रवाई, जो अधिनियम के असंगत न हो और आयोग को कठिनाई दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक तथा समीचीन हो, करने के लिए निर्देशित कर सकेगा।

8. **आदेशों तथा व्यवहार सम्बन्धी निर्देश जारी करना.**— अधिनियम तथा इन विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, आयोग, समय समय पर, इन विनियमों के कार्यान्वयन तथा उक्त

कार्यान्वयन के बारे में प्रक्रिया अपनाने तथा उसके प्रासंगिक अथवा सहायक मामलों के सम्बन्ध में आदेश और व्यवहार सम्बन्धी निर्देश जारी कर सकता है ।

9. निर्वचन.— इन विनियमों के निर्वचन से सम्बन्धित सभी विवादक आयोग द्वारा विनिश्चित किए जाएँगे तथा उन पर आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—

सचिव ।

{विनियम 5 (2) देखें}

5 मैगावाट की/तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए  
टैरिफ अवधारण संदर्भिकाएं

1. पूंजी लागत:—आयोग, टैरिफ अवधारण हेतु प्रज्ञायुक्त जाँच करते समय, परियोजना के निर्माण के समापन तक किए गए वास्तविक व्यय पर विचार करेगा। पूंजी लागत की संवीक्षा पूंजी लागत के औचित्य, वित्तीय योजना, निर्माणावधि ब्याज, प्रौद्योगिकी तथा अन्य सुसंगत साधनों के प्रयोग के आधार पर की जाएगी। तथापि परियोजना की पूंजी लागत की अधिकतम सीमा 6.5 करोड़ प्रति मैगावाट होगी।

2. क्षमता उपयोग कारक:—क्षमता उपयोग कारक की निचली सीमा 40 प्रतिशत होगी। प्रत्येक दशा में मानकीय पूरक खपत तथा पारेषण क्षति 0.5 प्रतिशत मानी जाएगी।

3. देयता साम्या अनुपात(डेविट-इक्यूटी-रेशिओ):—देयता साम्या अनुपात 70:30 होगा।

4. साम्या पर प्रतिफल (रिटर्न-ऑन-इक्यूट) साम्या पर प्रतिफल 14 प्रतिशत होगा।

5. ऋण पूंजी पर ब्याज:—ऋण पूंजी पर ब्याज भारत में अधिसूचित बैंक की चालू मूल उधार दर जमा ऐसा पूर्ववधरित अन्तर (मार्जिन), जो यथार्थ रूप में ऐसी दर को प्रतिक्षिप्त करता हो जिस पर बाजार में उधार लिया जा सकता हो।

6. कामकाजी पूंजी पर ब्याज:—कामकाजी पूंजी पर ब्याज भारत में अधिसूचित बैंक के चालू लघुकालिक मूल उधार दर के बराबर होगा। कामकाजी पूंजी में सम्मिलित होगा—

(क) एक मास का परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय,

(ख) वाणिज्यिक परिचालन की तारीख से 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धित इतिहासिक लागत की 1 प्रतिशत की दर से अनुरक्षण स्पेयर्स; तथा;

(ग) दो मास की बिल राशि के बराबर प्राप्तियां।

7. परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय:— 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ती सहित पूंजीगत व्यय का 1.5 प्रतिशत परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय होगा।

8. अवक्षयण.—परियोजना की परिचालन अवधि 40 वर्ष तथा अवक्षयण लागत का 90 प्रतिशत मानते हुए, अवक्षयण दर 2.25 प्रतिशत मानी जाएगी। केन्द्रीय आयोग के टैरिफ विनियमों के अनुसार अवक्षयण के लिए अग्रिम भी अनुज्ञात किया जा सकेगा।

9. शुल्क एवं प्रभार.—टैरिफ अवधारण के प्रयोजन के लिए, शुल्क एवं प्रभार चालू दरों पर अनुज्ञात होंगे। कर छूट, यदि कोई हो, के कारण टैरिफ में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाएगा।

10. ऋण अवधि.—ऋणों की वापसी की अवधि 10 वर्ष होगी।

11. सिंगल पार्ट टैरिफ.—लघु जल विद्युत परियोजनाओं का स्वरूप विशेष अविस्थिति पूर्ण तथा विद्युत भार कारक में व्यापक अस्थायित्व, परियोजना लागत तथा अन्य प्राचलों के होते हुए, आयोग सिंगल पार्ट टैरिफ पर विचार करेगा।

*[Authoritative English text of Government Notification No. H.P.E.R.C/428.— Dated 13<sup>th</sup> April, 2007 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].*

## HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION SHIMLA

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 13th April, 2007*

**No.HPERC/428.**— In super-session of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission's notification of even No. dated 30<sup>th</sup> November 2005, the following revised draft regulations for promoting the sale of power from renewable sources and co-generation and power procurement from renewable sources and co-generation by the distribution licensee within the State of Himachal Pradesh, which the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission proposes to make in exercise of the powers conferred under clauses (a),(b) and (e) of sub-section (1) of section 86 and sub-section(1) of section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, are hereby published, as required by rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005 and by sub-section (3) of section 181 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby; and, notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of



thirty days from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla – 171002

## DRAFT REGULATIONS:

**1. Short title, extent and commencement.**— (1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Power Procurement from Renewable Sources and Co-generation by Distribution Licensee) Regulations, 2007.

(2) These regulations shall extend to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

**2. Definitions.**—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003);
- (b) “Commission” means the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission;
- (c) “inter-connection point” and “inter-connection facilities”, shall have the meanings as assigned to them in the Power Procurement Agreement (PPA) entered into by the person generating energy from renewable sources and co-generation;
- (d) “renewable sources and co-generation” in this context means non-conventional renewable electricity generating sources such as mini/micro/small hydro power projects upto and including 25 MW capacity, wind, solar, biomass, urban/municipal waste, or other such sources as approved by the Central Government;
- (e) “State” means the State of Himachal Pradesh; and
- (f) the words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act; expressions used herein but not specifically defined in these regulations or in the Act but defined under any law, passed by a competent legislature and applicable to the electricity industry in the State shall have the meaning assigned to them in such law; expressions used herein but not specifically defined in the regulations or in the Act or any law passed by a competent legislature shall have the meaning as is generally assigned to them in the electricity industry.

**3. Promotion of renewable sources of energy.**—(1) Any person generating electricity from renewable sources and cogeneration, irrespective of installed capacity, shall have mandatory open access to any licensee's transmission system and/or distribution system or grid, as the case may be under the HPERC (Terms and Conditions of Open Access) Regulations, 2005. On an application from such person, the transmission licensee or the distribution licensee or the State Transmission Utility (STU), as the case may be, shall provide appropriate inter-connection facilities, and such facilities will be consistent with the grid connectivity standards as may be specified by the Authority:

Provided that the person generating energy from renewable sources and cogeneration shall bear the expenditure incurred for connectivity upto inter-connection point and the distribution licensee, the transmission licensee or the State Transmission Utility, as the case may be, shall bear the cost of augmentation, if any, of transmission/ sub-transmission system beyond the inter-connection point for evacuation of power.

(2) The Renewable Energy and Co-generation Producer shall provide to the distribution licensee, the transmission licensee or the State Transmission Utility, as the case may be, an interest free loan equivalent to 50% of the cost of works to be carried out for the evacuation of power beyond interconnection point, and for this purpose the estimates of the cost of works shall be based on the cost data approved by the Commission:

Provided that in case there are more than one such Renewable Energy and Co-generation Producers sharing the power evacuation system beyond the inter-connection point, the loan amount, based on the capital cost of the projects on prorata basis, shall be shared amongst the Renewable Energy and Co-generation Producers.

(3) The distribution licensee, the transmission licensee or the State Transmission Utility, as the case may be, shall repay the interest free loan to the Renewable Energy and Co-generation Producer(s) in five equal installments, spread over a period of 5 years, commencing from one year after the date of commissioning of the project.

(4) Priority shall be given for connectivity/transmission/wheeling of energy from renewable sources and co-generation through the grid.

(5) Banking of energy shall be permitted by the distribution licensee.

**4. Quantum of purchase of electricity from renewable sources.**—(1) Energy from renewable sources and co-generation available after the captive use and third party sale outside the State shall be purchased by the distribution licensee(s):

Provided that subject to the availability of renewable energy and co-generation within the area of a distribution licensee the quantum of purchase of energy from renewable sources and

co-generation by a distribution licensee, under these regulations shall be minimum 20% of its total consumption during a year;

*Explanation.*—For the purposes of this regulation the “quantum of purchase” would be the sum of all direct purchase from co-generation, generating stations based on renewable energy sources and purchase from any other licensee, which would arise from renewable sources and co-generation.

(2) The distribution licensee shall indicate, alongwith the sufficient proof thereof, the quantum of purchase of energy from renewable sources and co-generation for the ensuing year in the Annual Revenue Requirement (ARR) filing.

(3) The Commission may review the quantum of purchase of energy from renewable sources and co-generation by a distribution licensee once in every 3 years.

(4) Subject to supply constraints or any other uncontrollable factors, the Commission may, at the request of the distribution licensee, waive off the quantum of purchase laid down under sub-regulation(1).

**5. Determination of Tariff.**—(1) The tariff for the procurement energy from mini/micro/small hydro projects upto and including 25 MW by the distribution licensee shall be as per the prevalent hydro policy notified by the State Government .

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), the producers of renewable energy from mini/micro/small hydro projects upto and including 5 MW may apply to the Commission for determination of tariff and the Commission, while determining the tariff, shall consider the cost based benchmarks as given in Annexure to these regulations, and it shall be guided by the National Electricity Policy and Tariff Policy formulated by the Central Government under section 3 of the Act and by the principles and methodologies specified by the Central Commission and the terms and conditions of such tariff notified by the Central Commission:

Provided that the Commission may, for sufficient reasons and after exercising due diligence and applying prudency check, deviate from the terms and conditions of the generation tariff notified by the Central Commission:

Provided further that the Commission, while determining the tariff, shall, to the extent possible, permit an allowance based on technology, market risk, environmental benefits and social contribution etc. of the mini/micro/small hydro project.

(3) The benchmarks, as given in Annexure to these regulations, shall be reviewed once in three years.

(4) Subject to the cost based benchmarks to be laid down by the Commission, the tariff for other renewable sources and co-generation shall be such as the Commission may, by general or special order, direct, and, in doing so, the Commission shall be guided by the National Electricity Policy and Tariff Policy.

6. *Overriding effect.*—Notwithstanding anything contained contrary—

- (a) in the HPERC (Terms and Conditions Determination of Tariff) Regulations, 2004; and
- (b) in the HPERC (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2004;

framed by the Commission under section 181 of the Electricity Act, 2003, these regulations will have overriding effect.

7. *Power to remove difficulties.* — If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may, either *suo motu* or on an application made to it, do or undertake to do things, or by general or special order direct the licensee to take suitable action, not being inconsistent with the Act, which appears to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

8. *Issue of orders and directions.*— Subject to the provisions of the Act and these regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions with regard to the implementation of these regulations and procedure to be followed for such implementation and matters incidental or ancillary thereto.

9. *Interpretation.*—All issues arising in relation to interpretation of these regulations shall be determined by the Commission and the decision of the Commission on such issues shall be final.

By the order of the Commission,

Sd/-  
Secretary

[ (See regulation 5(2) ]

**BENCHMARKS FOR TARIFF DETERMINATION FOR MINI/MICRO/  
SMALL HYDRO PROJECTS UPTO AND INCLUDING 5 MW**

1. *Capital Cost.*— The Commission while exercising prudence check for tariff determination, shall take into account the actual expenditure incurred on the completion of the projects. The scrutiny of capital cost shall be based on the reasonableness of the capital cost, financing plan, interest during construction, use of technology and other relevant factors for determination of tariff. However maximum ceiling limit of the capital cost of the project shall be Rs.6.5 crore per MW.

2. *Capacity Utilization Factor.*—The lower ceiling limit of capacity utilization factor shall be 40%. The normative auxiliary consumption, and transformation losses shall be taken as 0.5 % each.

3. *Debt Equity Ratio.*—The debt equity ratio shall be 70:30.

4. *Return on Equity.*—The return on equity shall be 14%

5. *Interest on Loan Capital.*—Interest on loan capital shall be equal to the prevalent Prime Lending Rate of a Scheduled Bank plus a pre determined margin which realistically reflects the rate at which debt from the market can be raised.

6. *Interest on working capital.*—The rate of interest of working capital shall be equal to the prevalent short term Prime Lending Rate of a Scheduled Bank in India. The working capital shall comprise of,—

(a) operational and maintenance expenses for one month.

(b) maintenance spares @ 1% of the historical cost escalated @ 4% per annum from the date of commercial operation; and

(c) receivables equivalent to two months bill amount.

7. *Operation and Maintenance.*—The O&M cost shall be 1.5% of capital expenditure with 4% escalation every year.

**8. Depreciation.**—Considering the period of operation as 40 years and depreciation upto 90% of the cost of the project, the depreciation rate shall be taken as 2.25%. The advance against depreciation shall also be allowed as per the tariff regulations of the Central Commission.

**9. Taxes and Duties.**—Taxes and duties shall be allowed at prevailing rates for tariff determination purposes. Reduction in tariff on account of tax holiday, if any, shall be passed on to the consumers.

**10. Loan Period.**—The loan repayment period shall be taken as 10 years.

**11. Single Part Tariff.**—In view of site-specific nature of SHPs and wide variability in PLF, project cost and other parameters, the Commission shall consider single part tariff.